

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 1972/अग्रहायण 2, 1894

No. 500] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 1972/AGRAHAYANA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 23rd November 1972

S.O. 722(E)/15/IDRA/72.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Burn and Company, Limited, Calcutta, is engaged in the scheduled industries, namely, metallurgical and transportation industries;

And whereas the Central Government is of the opinion that the industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industries concerned and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman

1. Shri R. K. Sethi, Managing Director, National Industrial Development Corporation, Limited, New Delhi.

Members

2. Shri A. Bose, Special Officer and *ex-officio* Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta.

(1971)

3. Shri Sujit Banerji, Deputy Secretary, Ministry of Steel and Mines, (Department of Steel), New Delhi.
 4. Shri S. Majumdar, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
 5. Shri A. S. Nangia, Chief Marketing Manager, Project and Equipment Corporation, Limited, New Delhi.
 6. Shri B. G Roy, Technical Adviser, Industrial Reconstruction Corporation of India, Limited, Calcutta.
 7. Shri R. Das, Management Accountant, Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta.
 8. Shri A. K. Srivastava, Superintendent, Mechanical Workshop (Carriage and Wagons), Eastern Railways, Calcutta.
 9. Shri M. P. Rajagopalan, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.
 10. Shri A. N. Roy, Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta.
2. The above body shall submit its report within a period of eight weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 2(21)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1972

कां.प्र. 722(प्र)/15/आई. डी. आर. ए. 72. —यतः मैसर्स बन एण्ड कंपनी, लिमिटेड, कनका नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योगों अर्थात् धातुकर्मक और परिवहन उद्योगों में लगा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस रूप में चलाया जा रहा है जो संबंधित अनुसूचित उद्योगों और लोक हित के लिए अत्यन्त हानिकर है;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों में पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ एतद्वारा एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे

अध्यक्ष

1. श्री आर. के. सेठी,
प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड,
नई दिल्ली ।
सदस्य
2. श्री ए. बी. बाम,
विशेष अधिकारी एवं पदेन सचिव,
बंद और अख्यवस्थित उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।
3. श्री मुजीब बनर्जी,
उप सचिव,
उत्पात और खान मंत्रालय,
(इस्पात विभाग),
नई दिल्ली ।

सदस्य

4. श्री एस० मजुमदार,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।
5. श्री ए० एस० नागिया,
मुख्य विपणन प्रबन्धक,
परियोजना और उपस्कर निगम, लिमिटेड,
नई दिल्ली ।
6. श्री बी० जी० राय,
तकनीकी सलाहकार,
भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड,
कलकत्ता ।
7. श्री आर० दास,
प्रबन्ध लेखापाल,
त्रेथवेट एण्ड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
कलकत्ता ।
8. श्री ए० के० श्रीवास्तव,
अधीक्षक,
मशीन वर्कशॉप (कॉरियेज और बेगन्स),
पूर्वी रेलवे,
कलकत्ता ।
9. श्री एम० पी० राजगोपालन,
उपेष्ट लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग),
नई दिल्ली ।
10. श्री ए० एन० राय,
प्रदेशिक श्रम आयुक्त (केंद्रीय),
कलकत्ता ।

2 उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

[सं० 2/21/72-सी० यू० सी०]

क० एम० भटनागर, सचिव ।

